आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 04.07.2022 से 09.07.2022)

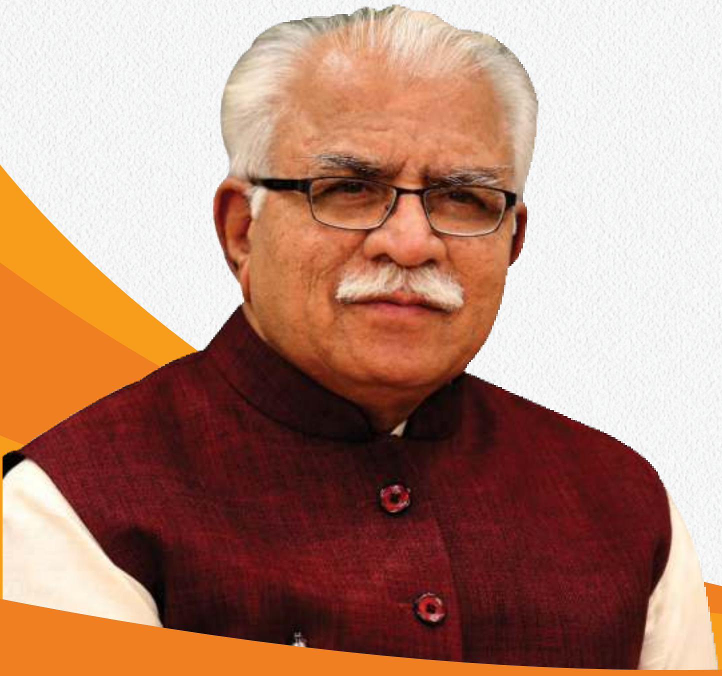

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

जिला उपायुक्तों के साथ लैंड बैंक के संबंध में बैठक

(दिनांक 05.07.22)

विषय: जिला उपायुक्तों के साथ लैंड बैंक के संबंध में बैठक।

प्रभाव: माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक कर राज्य सरकार की लैंड बैंक नीति के तहत जल्द से जल्द जिले की सम्पूर्ण भूमि का डाटा तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, चिन्हित भूमि की जीआईएस मैपिंग करवाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि सभी डाटा डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री जी ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले की सम्पूर्ण भूमि, चाहे वह हरियाणा सरकार की मलकीयत वाली भूमि हो, ग्राम पंचायत, बोर्ड या निगम तथा निजी भूमि हो, का भी विस्तृत आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना, लार्ज स्केल मैपिंग योजना के तहत की जा रही भूमि की मैपिंग तथा शहरी क्षेत्रों में की जा रही ड्रोन मैपिंग का कार्य भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए, तभी जिले की वास्तविक भूमि का आकलन किया जा सकेगा।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के पास पड़ी अनुपयोगी भूमि अब सरकार के नाम होंगी और उन्हें भूमि बैंक में जमा किया जाएगा। जमीन की मलकीयत हरियाणा सरकार की होगी। लैंड बैंक में एकत्रित भूमि का उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए आसानी से किया जा सकेगा।

अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की पहली बैठक

(दिनांक 07.07.22)

विषय: अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की पहली बैठक।

प्रभाव: आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्स मॉनिटरिंग ग्रुप की पहली बैठक में भाग लिया। यह बैठक मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अटेंड की। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूश गोयल, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैश्णव भी मौजूद थे।

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम से प्रदेश में औद्योगिकरण और लॉजिस्टिक को मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक तरक्की होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। उन्हीं की विजन से देशभर में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाले हैं। हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एनसीआर का क्षेत्र हरियाणा में होने की वजह प्रदेश औद्योगिकरण का हब बना है। उद्योग की दृष्टि से हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक होने का हरियाणा के उद्योगों को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि देश के दो बड़े कॉरिडोर– वेस्टर्न

इकनॉमिक कॉरिडोर और इस्टर्न इकनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहे हैं वे हरियाणा से होकर गुजरेंगे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री जी ने जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा के नांगल चौधरी में प्रस्तावित इंटीग्रेटिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब 886 एकड़ में बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सड़क, पानी और बिजली आदि का काम शुरू हो गया है। इसे पूरा करने का टारगेट तय कर दिया है। इसे निष्चित समय पर पूरा किया जाएगा। इससे जुड़ी रेलवे लाइन का अवार्ड भी सुना दिया है। 40 प्रतिशत भूमि का कब्जा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दे दिया है बाकि भूमि का कब्जा 15 अगस्त तक ले लिया जाएगा।

इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) हिसार की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए 1605 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है। आईएमसी, हिसार का मास्टर प्लान भी तैयार हो चुका है। पर्यावरण क्लियरेंस को भी जल्द पूरा करवाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट भी गति से आगे बढ़ रहा है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने यमुनानगर के कलानौर में इनलैंड कंटेनर डिपो की रखी मांग भी रखी।

प्रगति रैली (चरखी दादरी)

(दिनांक 08.07.22)

विषय: प्रगति रैली (चरखी दादरी)।

प्रभाव: मुख्यमंत्री जी ने आज चरखी दादरी में आयोजित प्रगति रैली में जिला को करीब 1100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की शुरूआत की।

मुख्यमंत्री जी ने चरखी दादरी से अपना 32 साल पुराना संबंध बताते हुए कहा कि उनके

दिल में इस पिछड़े क्षेत्र को विकसित करने की कसक थी, आज वे विधायक, सांसद तथा आम आदमी की डिमांड पर लगभग 600 मांग पूरी करने की घोषणा कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से दादरी का रिंग रोड बाईपास, इमलोटा में बस स्टैंड, बाढड़ा में चालक प्रशिक्षण, दादरी से खैरड़ी रोड़ का निर्माण, झोझू–कादमा–सतनाली रोड़, दादरी शहर सीवरेज का सुधार इत्यादि शामिल हैं।

इससे पूर्व , मुख्यमंत्री जी ने चरखी दादरी जिला में 350 करोड़ रूपये की लागत की 17 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवम शिलान्यास किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चरखी दादरी भले ही हरियाणा का सबसे आखिरी जिला बनाया गया हो लेकिन विकास की पंक्ति में आखिरी नहीं रहने देंगे। जिस रफ्तार से यहां विकास कार्य हो रहे हैं, उससे यह जिला पूर्ण जिले का रूप ले रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस जिले में जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने 200 घोषणाएं की थी, जिनमें से 70 प्रतिशत पूरी हो चुकी है, बाकि बची हुई घोषणाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है।

रैली के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी सरकार बिना पर्ची और बिना खर्ची के सिद्धांत पर काम कर रही है। अभी हरियाणा द्वारा पुलिस के 5 हजार सिपाहियों व इतने ही क्लर्कों की भर्ती की गई है। इसमें पूर्ण पारदर्शिता बरती गई है। मुख्यमंत्री ने रैली में बैठे लोगों से सवाल पूछा कि नौकरी के नाम पर किसी ने कोई पैसा लिया हो तो

साप्ताहिक सूचना पत्र

सीधे उन्हें बता सकते हैं, इस पर लोगों ने हाथ उठाकर इनकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में 11 भर्ती न्यायालय द्वारा रदद हुई, लेकिन हमारी सरकार में कोर्ट से कोई भर्ती रद्द नहीं हुई बल्कि हमने स्वयं यदि कोई भ्रष्टाचार व पेपर लीक होने की जानकारी मिली तो कार्रवाई की है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र एक अनूठा दस्तावेज है जिसमें हर परिवार का डाटा उपलब्ध है और जिसमें परिवार के हर सदस्य की पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग बेरोजगारी पर झूठे आंकड़े प्रचारित कर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं । जबकि पीपीपी के डाटा के अनुसार 15–19 आयु वर्ग के लगभग 25.50 लाख युवाओं में 24

लाख शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी प्रकार 20–24 आयु वर्ग में लगभग 26 लाख है जिसमें 15 लाख विद्यार्थी हैं। इस प्रकार बेरोजगारी दर 15–19 आयु वर्ग में 2.33 प्रतिशत तथा 20–24 आयु वर्ग में 11.6 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैने पिछले सरकारों में सीएलयू व ट्रांसफर के नाम पैसा लेने वालों को बेरोजगार किया है। अब यह व्यवस्था ऑनलाईन कर दी है। पैसे के दम पर अब कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने वजीफा, पैंशन, राशन में घपले पकड़ने का कार्य करते हुए व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ नौकरियों में पारदर्शिता से कार्य कर रही है ।

उन्होंने कहा की दादरी जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ कर रहा है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक

(दिनांक 09.07.22)

विषय: उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक।

प्रभाव: माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जयपुर पहुंचकर उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30 वीं बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा से जुड़े विशयों और मांगो को उठाया। जिसके तहत केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को बड़ी सौगात दी गई है। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने घोषणा की कि हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन दी जाएगी।

मुख्यमंत्री शजी ने इस घोषणा के लिए समस्त हरियाणा वासियों की ओर से गृहमंत्री जी का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के लिए नए अतिरिक्त भवन के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। अब गृहमंत्री की घोषणा के बाद जल्द ही इसका काम शुरू हो पाएगा।

दरअसल वर्ष 2026 में नया परिसीमन प्रस्तावित है, जिसके आधार पर वर्ष 2029

साप्ताहिक सूचना पत्र

में लोकसभा व विधानसभा चुनाव होंगे। अनुमान है कि नये परिसीमन में हरियाणा की जनसंख्या के अनुसार विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 126 तथा लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 14 होगी। हरियाणा विधानसभा में इस समय 90 विधायक हैं। मौजूदा भवन में इन 90 विधायकों के बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, इस भवन का विस्तार किया जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि यह हैरीटेज बिल्डिंग है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने उत्तर क्षेत्रीय परिशद की 30वीं बैठक में सतलुज–यमुना लिंक नहर, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति, पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से को बहाल करने और हरियाणा विधानसभा के लिए नए अतिरिक्त भवन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को पुरज़ोर तरीके से उठाया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के साथ–साथ अंतर्राज्यीय तथा केन्द्र व राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों को समयबद्ध ढंग से सुलझाने में सहायक सिद्ध होगी। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा देश का एक छोटा–सा राज्य है। परन्तु देश की अर्थव्यवस्था में इसका उल्लेखनीय योगदान है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 74 हजार 635 रुपये है, जो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। आर्थिक विकास दर के मानदण्डों पर भी हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा उत्तर भारत में पहले स्थान पर है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सतलुज–यमुना लिंक नहर के निर्माण कार्य को पूरा करना हरियाणा और पंजाब राज्यों के बीच अत्यंत पुराना और गंभीर मसला है। यह नहर न बनने के कारण रावी, सतलुज और ब्यास का अधिशेष, बिना चौनल वाला पानी पाकिस्तान में चला जाता है। हरियाणा को भारत सरकार के 24 मार्च, 1976 के आदेशानुसार रावी–ब्यास के सरप्लस पानी में भी 3.50 मिलियन एकड़ फुट हिस्सा आबंटित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एस.वाई.एल. मुद्दे को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 18 अगस्त, 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, पंजाब आगे कार्रवाई नहीं कर रहा है।